दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रिट याचिका (सिविल) सं. 11941/2009

निर्णय सुरक्षित: 24 सितम्बर, 2009
निर्णय दिया गया: 6 अक्टूबर, 2009

प्रोदीप कुमार मंडल .... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री संजय सहरावत, अधिवक्ता।

बनाम

भारत का संघ और अन्य .... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अनिल गौतम, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता1।
श्री नरेश कौशिक के साथ सुश्री अदिति गुप्ता और सुश्री अमिता चौधरी, अधिवक्ताओं, यूपीएससी के लिए।

कोरमः
माननीय श्री न्यायाधीश मदन बी. लोकुर
माननीय श्री न्यायाधीश ए.के. पाठक

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ
2. रिपोर्टर के पास प्रेषित किया जाना है या नहीं? हाँ
3. क्या निर्णय को डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हाँ

<u>न्या., ए.के. पाठक</u>

1. दिनाँक 21 मई, 2009 के आदेश के माध्यम से, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (इसके बाद न्यायाधिकरण के रूप में संदर्भित) ने याचिकाकर्ता के मूल आवेदन संख्या 1433/2007 को खारिज कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका दायर की है जिसमें अनुरोध किया गया है कि न्यायाधिकरण के विवादित आदेश को अपादस्त कर दिया जाए और मू.आ. की अनुमति दी जाए।

2. मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स, जैसा कि रिकॉर्ड से सामने आता है, यह इंगित करता है कि याचिकाकर्ता केंद्रीय सचिवालय सेवा में प्रत्यक्ष भर्ती सहायक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के रूप में शामिल हुआ था। इसके बाद, वह अनुभाग अधिकारी ग्रेड लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2003 सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के पद पर लागू भर्ती नियमों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग (सं.लो.से.आ.) द्वारा आयोजित किया गया अनुभाग अधिकारी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा नियमों के अनुसार, एक भर्ती वर्ष में 50 प्रतिशत रिक्तियों को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा. द्वारा से भरा जाना था। वर्ष 2003 की उक्त परीक्षा में, संघ लोक सेवा आयोग ने अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए 243 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया। इसके बाद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी. एंड टी.), कैडर

नियंत्रण प्राधिकरण होने के नाते, संघ लोक सेवा आयोग से अनारक्षित श्रेणी के दोहराए गए उम्मीदवारों की अतिरिक्त सूची जारी करने का अनुरोध किया। इस अनुरोध के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने 3 अनारक्षित उम्मीदवारों की एक अतिरिक्त सूची जारी की, जिनके नाम श्री जसबीर सिंह नेगी, श्री रंजीत कुमार श्रीवास्तव और श्री अभय नंदन मिश्रा हैं।

3. याचिकाकर्ता एक अनुसूचित जाति (अ.जा.) उम्मीदवार है। दावा किया कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार, जिन्होंने अनारक्षित उम्मीदवारों के बराबर सामान्य मानकों के बराबर अंक प्राप्त किए थे, उन्हें अनारक्षित रिक्तियों के खिलाफ समायोजित नहीं किया गया था। यदि समायोजन किए जाते, तो अनुसूचित जाति के रिक्त पद खाली हो जाते और याचिकाकर्ता को ऐसी रिक्तियों में से किसी एक के खिलाफ समायोजित किया जा सकता था। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सूची में अंतिम अनारक्षित उम्मीदवार श्री कुमार मनोज कश्यप को क्रम संख्या 210 में दिखाया गया था। उनके नीचे केवल अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को रखा गया था। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2007 को प्रस्तुत अनुपूरक सूची के अनुसार, श्री जसबीर सिंह नेगी, श्री रंजीत कुमार श्रीवास्तव और श्री अभय नंदन मिश्रा की सिफारिश की गई थी और वे अनारक्षित श्रेणी से संबंधित थे। श्री जसबिर सिंह नेगी और श्री रंजीत कुमार श्रीवास्तव को सीरियल नंबर 212 और 214 के बीच रखा गया था और जहां तक श्री अभय नंदन मिश्रा का संबंध है, उन्हें सीरियल नंबर 222

और 223 के बीच रखा गया था, जिससे वे अंतिम अनारक्षित उम्मीदवार बन गए। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि क्रम संख्या 222 से ऊपर के अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को, उच्च अंक प्राप्त करने के बाद में अनारक्षित रिक्ति के खिलाफ समायोजित किया जाना आवश्यक था और ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति का उम्मीदवार होने के नाते अनुसूचित जाति श्रेणी में अनुभाग अधिकारी के पद के लिए पात्र होता।

4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी का मामला यह था कि अंतिम अनारक्षित उम्मीदवार को क्रम संख्या 210 पर रखा गया था जिसे बाद में श्री ए.एन. मिश्रा के स्तर पर लाया गया जो एक अनारक्षित दोहराए जाने वाले उम्मीदवार थे। 12 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में क्रम संख्या 210 और श्री ए.एन. मिश्रा के बीच के उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के हकदार नहीं थे क्योंकि उन्होंने सूची में उस पद को आसान मानदंडों पर प्राप्त किया था। उन्होंने अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित 200 अंकों के सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा. के लिखित भाग में निर्धारित मानक को पूरा नहीं किया। क्रमिक संख्या 210 से परे सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छूट वाले मानक के अनुसार सूची में रखा गया था, तदनुसार, 210 की रैंक से नीचे के अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को श्री ए.एन. मिश्रा तक अनारक्षित रिक्तियों के खिलाफ समायोजित नहीं किया जा सकता था। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों ने पहले

से ही परीक्षा नियमों के अनुसार छूट प्राप्त मानक का लाभ उठाया था और उन्हें आरक्षित पदों के खिलाफ रखा जाना था। इसलिए वे अनारक्षित पदों का दावा नहीं कर सकते।

5. न्यायाधिकरण ने इस संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के रिकॉर्ड मांगे 4 प्रश्न अनारक्षित की अंक सूची सहित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा. और 11 अ.जा. और 1.अ.ज.जा. उम्मीदवारों को यह सत्यापित करने के लिए कि क्या संघ लोक सेवा आयोग अ.जा./ अ.ज.जा. उम्मीदवारों के मामले में मानकों में ढील दी गई थी क्रम संख्या 210 के नीचे या नहीं। न्यायाधिकरण ने पाया कि 200 अंकों की अनारक्षित श्रेणी के लिए मानक सेट लिखित परीक्षा, सभी 11 अ.जा. के मामले में ढील दी गई थी और 1 अ.ज.जा. उम्मीदवार, जिन्हें अंतिम से नीचे रखा गया था अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार श्री कुमार मनोज कश्यप। न्यायाधिकरण ने पाया कि ये 11 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में कम अंक प्राप्त किए थे। न्यायाधिकरण ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अतिरिक्त शपथ पत्र पर विचार किया इसके समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेखों को भी और संक्षेप में श्रेणी से अनारक्षित, अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों की स्थिति सं. 210 से आगे, जो तैयार संदर्भ के लिए है - निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया गयाः

रैंक सं.	**उम्मीदवार का नाम**	**समुदाय**	**श्रेणी के अंतर्गत योग्य**
210	कुमार मनोज कश्यप	सामान्य	मुख्य में सामान्य सूची

211	इंदर जीत	अ.जा.	अ.जा. में आराम करें। मुख्य सूची में मानक
212	शक्ति शमशेर	अ.जा.	-करें।
213	बिप्लब कुमार नस्कर	अ.जा.	-करें।
214	जसबिर सिंह नेगी	सामान्य	सामान्य में पूरक सूची
215	रंजीत कुमार श्रीवास्तव	सामान्य	सामान्य में पूरक
216	कुलदिप कुमार	अ.जा.	अ.जा. में आराम करें। मुख्य सूची में मानक
217	एम. जेना	एससी अ.जा.	-करें।
218	सुनील कुमार	एससी अ.जा.	-करें।
219	राजेश कुमार	एससी अ.जा.	-करें।
220	अमरीश कुमार	अ.जा.	-करें।
221	बिपिन कुमार हेम्ब्रोम	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. में आराम करें। मुख्य सूची में मानक
222	लक्ष्मी कांत हलदर	अ.जा.	अ.जा. में आराम करें। मुख्य सूची में मानक
223	राज कुमार	अ.जा.	-करें।
224	रोहतास भैंखर	अ.जा.	-करें।

225	अभय नंदन मिश्रा	सामान्य	सामान्य में पूरक सूची
226	सहदेव सिंह	अ.जा.	अ.जा. में आराम करें। मुख्य सूची में मानक
227	प्रदीप कुमार पाल	अ.जा.	-करें।
228	दीन दयाल	अ.जा.	-करें।
229	लखमी चंद	अ.जा.	-करें।
230	राजिंदर कुमार	अ.जा.	-करें।
231	रचना	अ.जा.	-करें।
232	धारकत रुंगसुंग लुइकांग	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. में आराम करें। मुख्य सूची में मानक
233	आशीष कुमार ताराचंद	अ.जा.	अ.जा. ने दी राहत मुख्य सूची में मानक
234	स्नेह लता	अ.जा.	-करें।
235	शंकर लाल बैरवा	अ.जा.	-करें।
236	सुधीर बाबू मोटाना	अ.जा.	-करें।
237	नरेश कुमार	अ.जा.	-करें।

238	निठाली राम	अ.जा.	-करें।
239	सुरेंद्र कुमार	अ.जा.	-करें।
240 241	सुनीता राजेश कुमार गुजर	अ.जा. अ.जा.	-करें। -करें।
242	अंजन बिस्वास	अ.जा.	-करें।
243	योगीश आर. पटेल	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. में आराम करें मुख्य सूची में मानक
244	योगिंदर कुमार	अ.जा.	अ.जा. ने दी राहत मुख्य सूची में मानक

6. न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित करने के लिए परीक्षा के नियम 8 को भी ध्यान में रखा कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को अनारक्षित उम्मीदवारों के रूप में नही माना जाता है जैसा कि उन्होंने नीचे दी गई सूची में अपना स्थान

प्राप्त किया था श्री कुमार मनोज कश्यप के नीचे की सूची में, मानकों में ढील के आधार पर और इस प्रकार अनारक्षित रिक्तियों के खिलाफ नहीं रखा जा सकता था।

7. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। हम न्यायाधिकरण के विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं, जो उसके समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के साथ-साथ नियम की स्थिति के आधार पर पारित किया गया है।

8. परीक्षा नियमों का नियम 8 इस प्रकार हैः

> "8(i) परीक्षा के बाद, आयोग द्वारा उम्मीदवारों को योग्यता के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा जैसा कि प्रत्येक उम्मीदवार को अंत में दिए गए कुल अंकों द्वारा प्रकट किया गया है और उस क्रम में आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य पाए जाने वाले इतने उम्मीदवारों को आवश्यक संख्या तक प्रत्येक श्रेणी के लिए चयन सूची में शामिल आदेश के लिए अनुशंसित किया जाएगा।
>
> (ii) किसी भी अनुसूची जाति या अनुसूची जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को आयोग द्वारा अनुसूची जाति और अनुसूची जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक, परीक्षा में योग्यता के क्रम में उनके रैंक के बावजूद, प्रत्येक श्रेणी के लिए चयन सूची में शामिल आदेश के लिए इन उम्मीदवारों की योग्यता के अधीन, मानक में ढील दी जा सकती है।
>
> बशर्ते कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जिन उम्मीदवारों की आयोग द्वारा परीक्षा के किसी भी चरण में पात्रता या चयन मानदंड में कोई छूट/रियायत का सहारा लिए बिना सिफारिश की गई है, उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ समायोजित नहीं किया जाएगा।

9. ऊपर उद्धृत परंतुक का उप-नियम का (ii) के प्रावधान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार किसी

भी छूट पात्रता मानदंड का सहारा लिए बिना योग्यता सूची में अपना स्थान प्राप्त करता है तो वह एक अनारक्षित पद के लिए पात्र होगा। इस मामले में, श्री कुमार मनोज कश्यप से नीचे दिखाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों ने मानकों में ढील के आधार पर चयन सूची में स्थान प्राप्त किया था और वे अनारक्षित पद पर अपनी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते।

10. न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी द्वारा दायर जवाबी शपथ पत्र/अतिरिक्त शपथ पत्र में ली गई याचिका के समर्थन में उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड के आधार पर इस संबंध में एक स्पष्ट निष्कर्ष वापस कर दिया है। तदनुसार, हमारे पास प्रत्यर्थी द्वारा की गई याचिका पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है जो परीक्षा के रिकॉर्ड द्वारा समर्थित है।

11. हम न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए विचार में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं कि से नीचे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार। श्री कुमार मनोज कश्यप अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्त होने के योग्य नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उस पद को मानकों में ढील के आधार पर प्राप्त किया था। इन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा की लिखित परीक्षा में अनारक्षित उम्मीदवारों की तुलना में कम अंक प्राप्त किए थे और इस प्रकार खंड अधिकारी के अनारक्षित पद के लिए योग्य या समायोजित होने के पात्र नहीं थे।

12. यहाँ यह उल्लेख करने योग्य है कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंडों के मानक में ढील दिए जाने के बाद भी याचिकाकर्ता का नाम चयन सूची में उल्लेख नहीं मिलता है।

13. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में हम इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

14. बर्खास्त कर दिया।

न्या. ए. के. पाठक

न्या. मदन बी. लोकुर

अक्टूबर 6, 2009
गा

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*